



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2005/फाल्गुन 12, 1926

No. 27]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2005/PHALGUNA 12, 1926

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2005

सं. 3-57/2005 बी एचडी सी एस.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (के) के प्रावधानों और धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा फाइल सं. 13-1/2004-आरईएसटीजी से निर्गत दिनांक 9-1-2004 की अधिसूचना सं. 39 [का.आ. सं. 44(अ) तथा 45(अ)] के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के पैरा (ii), (iii) तथा (iv), धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा "दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अन्तरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13)" (जिसे यहां इसके बाद "प्रमुख विनियम" कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :

- (i) यह विनियम "दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अन्तरसंयोजन (पहला संशोधन) विनियम, 2005 (2005 का 2)" कहा जाएगा ।
- (ii) यह विनियम सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।

2. प्रमुख विनियम के विनियम 3 के खण्ड 7 में '90 दिन' शब्द तथा अंक के स्थान पर '120 दिन' शब्द और अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. इस विनियम के अनुबंध 'क' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रमुख विनियम में संशोधन करने का कारण स्पष्ट किया गया है ।

आदेशानुसार,

डॉ. हर्षवर्धन सिंह, सचिव एवं प्रधान सलाहकार

[विज्ञापन-3/4/असाधारण/142/04]

अनुबंध - क**व्याख्यात्मक ज्ञापन**

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने "दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अन्तरसंयोजन विनियम 2004" (2004 का 13) अधिसूचित किया था और यह विनियम 10 दिसम्बर, 2004 से प्रभावी हुआ था। इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी ब्राडकास्टर्स/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा उनके एजेंट/मध्यस्थ, जिनके माध्यम से वे सिगनल मुहैया कराते हैं, से अपेक्षा की गई है कि वे किसी ऐसे संव्यवहार अथवा कार्यकलाप में लिप्त नहीं होंगे अथवा वे कोई ऐसा समझौता या व्यवस्था नहीं करेंगे, जिसमें टीवी चैनलों के किसी वितरक से ऐसे अनन्य करार करना भी शामिल हैं, जिससे टीवी चैनलों के किसी अन्य वितरक के साथ भेदभाव होता हो। पूर्व की संविदाओं के मामले में अन्तरसंयोजन करारों में भेदभाव न करने से संबंधित इन प्रावधानों को लागू करने के लिए 90 दिन की अवधि प्रदान की गयी थी। पुरानी संविदाओं के लिए 90 दिन की यह अवधि पुनः विचार-विमर्श करने तथा उन्हें नए विनियमों के अनुरूप बनाने के लिए दी गयी थी।
2. एक ब्राडकास्टर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसमें अनुरोध किया गया था कि इस अन्तरण अर्वाधे को और 60 दिनों के लिए बढ़ाया जाए ताकि सभी करारों को विनियमों के अनुरूप बनाया जा सके। अवधि बढ़ाने के लिए जो कारण दिए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :
 - (क) ब्राडकास्टर्स ने टीवी चैनलों के विभिन्न वितरकों के साथ 6,000 से ज्यादा संविदाएं की हैं और ये संविदाएं अलग-अलग समय पर की गई हैं। उपर्युक्त के अलावा अन्तरसंयोजन विनियम लागू होने से पूर्व उन्होंने कई नए चैनल शुरू किए हैं और विभिन्न ऑपरेटरों के साथ परिशिष्टियों/संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं।
 - (ख) वे अब अपनी विभिन्न संविदाओं तथा परिशिष्टियों को अन्तरसंयोजन विनियम के अनुरूप अंतरित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा, कई आन्तरिक संगठनात्मक कार्य किए जा रहे हैं ताकि यह अन्तरण पूरी तरह सुगम हो। ये कार्य इस प्रकार हैं:
 - भारत में अपने चैनलों के वितरण के लिए एक नीति बनाना और वितरण के जुड़े कार्मिकों को वितरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के हर पहलू के संबंध स्पष्ट अनुदेश देना और उन्हें कंपनी की स्थिति बताना ताकि सभी कार्य अन्तरसंयोजन विनियम के अनुरूप सुनिश्चित हों।
 - वर्तमान संविदाओं तथा परिशिष्टियों की समीक्षा करना। वितरण नीति को अंतिम रूप देने के बाद वर्तमान संविदाओं तथा परिशिष्टियों को संशोधित किया जाएगा ताकि उन्हें इस नीति के अनुरूप बनाया जा सके। तत्पश्चात अपेक्षित

सीमा तक संशोधित किए गए फार्मेट में संविदाओं पर पुनः हस्ताक्षर किया जाएगा और इसके लिए अपने सहयोगियों के साथ विचार विमर्श भी करना होगा।

- देश भर में वितरण से जुड़े कार्मिकों तथा वितरकों के लिए पहले ही कई कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं ताकि उन्हें अन्तरसंयोजन विनियम के प्रावधानों को समझने में सहायता प्राप्त हो। इन कार्यशालाओं से प्राप्त जानकारी (इनपुट) का इस्तेमाल बकाया मुद्दों तथा प्रश्नों का समाधान करने के लिए किया जाएगा। वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के निष्पादन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में कंपनी के एकजीक्यूटिवों को विस्तार से समझाया जा रहा है।
- अन्तरसंयोजन विनियम के सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए कंपनी द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित सभी नए कार्यों को सुगम बनाने के लिए संगठनात्मक प्रक्रिया तथा पद्धति को परिभाषित किया जा रहा है।

3. प्राधिकरण ने इस अन्तरण अवधि को और 60 दिन के लिए बढ़ाने के अनुरोध पर विचार किया और परामर्श करने के अपने दृष्टिकोण के अनुसार इसने अन्तरण अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने के प्रस्ताव पर टिप्पणियां प्राप्त करने का निर्णय किया। तदनुसार 11 फरवरी, 2005 को एक प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें 18 फरवरी, 2005 तक इस मामले में टिप्पणियां मांगी गईं। इस मुद्दे पर निम्नलिखित प्रमुख टिप्पणियां प्राप्त हुईं :

(क) जयपुर केबल तथा ब्राडबैंड सोसायटी ने कहा है कि अन्तरण अवधि बढ़ाने से उन केबल चैनल के वितरकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने ब्राडकास्टर/एमएसओ के एकाधिकार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है। ज्यादा समय देने से ब्राडकास्टर/एमएसओ को परिस्थितियां अपने पक्ष में करने का समय मिलेगा। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा की शुरुआत होने में विलम्ब होगा। इसने आगे यह भी कहा कि जयपुर में केवल एक एमएसओ है और यह कनेक्टिविटी एमाउंट बढ़ाकर केबल नेटवर्क हथिया रहा है। अन्तरण अवधि को 60 दिन बढ़ाने का आशय यह होगा कि ब्राडकास्टर, केबल ऑपरेटर को 150 दिन तक डिकोडर नहीं देगा और बिना पे चैनलों के 150 दिन तक सेवा देते रहना संभव नहीं है।

(ख) केबल ऑपरेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित कारणों से आपत्ति व्यक्त की है :

- सभी प्रमुख ब्राडकास्टरों ने वितरण के लिए एक दूसरे के साथ समझौता किया हुआ है, जिसके अंतर्गत वे संयुक्त वितरण कर्मियों से समूहों में चैनलों का वितरण कर रहे हैं।
- यह कहना सही नहीं है कि वे अपनी संविदाओं को 90दिन के भीतर नई शर्तों के अनुसार संशोधित करने में असमर्थ हैं, क्योंकि ब्राडकास्टरों के

पास बहुत बड़ा वितरण विभाग होता है, जिसमें वितरण प्रमुख, रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर तथा प्रत्येक प्रमुख नगर में वितरण एक्जीक्यूटिव शामिल होते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक बड़े शहर में वितरण कंपनियां हैं, जो एलसीओ के साथ व्यवहार करते हैं। इस प्रकार निचले स्तर पर एक वितरक को 90 दिन में 40-50 संविदाओं से ज्यादा पर कार्रवाई नहीं करनी है।

- ब्राडकास्टर, वर्तमान ऑपरेटरों के साथ हुए अपनी संविदाओं को संशोधित करने पर कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं और वे प्रत्येक क्षेत्र में न्यूनतम गारंटी एजेंटों को नियुक्त करके अपनी कनेक्टिविटी 40-60% बढ़ाने के केवल नेटवर्कों पर दबाव डाल रहे हैं। 60 दिन की अवधि और बढ़ाने से इन न्यूनतम गारंटी एजेंटों और उनसे सम्बद्ध एनएसओएस को वर्तमान केवल ऑपरेटरों से अधिकतम लाभ उठाने का मौका मिलेगा।

4. प्राधिकरण ने यह देखते हुए कि यदि प्राधिकरण को भेदभावपूर्ण अन्तरसंयोजन करार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो ब्राडकास्टर/मल्टी सिस्टम ऑपरेटर/उनके एजेंट/मध्यस्थ को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका देने और उसे ठीक करने के लिए इस विनियम द्वारा प्रदान किए गए 30 दिन की अतिरिक्त अवधि को पर्याप्त समझा है। इसे उन्हें संविदा को अन्तरसंयोजन विनियम के अनुरूप बनाने का अवसर प्राप्त होगा।

5. यद्यपि प्राधिकरण ने अन्तरण अवधि के लिए पहले केवल 90 दिनों का अनुमोदन किया था परन्तु ब्राडकास्टरों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों तथा अब तक उठाए गए कदमों को देखते हुए और 30 दिन के लिए समय बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि यह केवल एक बारगी किया जाने वाला प्रावधान है और इसका कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होगा। दूसरी ओर यदि सभी तैयारियां पूरी नहीं होती हैं तो इस पर अनावश्यक मुकदमेबाजी हो सकती है।

6. इस प्रकार, प्रस्ताव तथा आपत्तियों पर विचार करने के बाद प्राधिकरण ने अन्तरण अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का निर्णय लिया है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2005

No. 3-57/2005/B&CS.—In exercise of the powers conferred by Section 36, and paras (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of Sub-section (1) of Section 11 of the Telecommunication Regulatory Authority of India Act, 1997, read with the Notification No. 39 [S.O. Nos. 44(E) and 45 (E)] dated 09-01-2004 issued from file No. 13-1/2004-Restg by the Government of India under clause (d) of Sub-section (1) of Section 11 and proviso to clause (k) of Sub-section (1) of Section 2 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India hereby amends the Telecommunication (Broadcasting and

Cable Services) Interconnection Regulation, 2004 (13 of 2004) (hereinafter called the "Principal Regulation"), as follows, namely :—

1. Short title, extent and commencement:
 - (i) This regulation shall be called "The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (First Amendment) Regulation 2005" (2 of 2005)".
 - (ii) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
2. The words and figures "120 days" shall substitute the words and figures "90 days" in clause (7) of regulation 3 of the Principal Regulation.
3. This regulation contains at Annex A, an Explanatory Memorandum that explains the reasons for this amendment to the Principal Regulation.

By Order,

Dr. HARSHA VARDHANA SINGH, Secy.-cum-Principal Advisor

[Advt.-3/1/Exty./142/04]

Annex. - A

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Telecom Regulatory Authority of India had notified "The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation 2004" (13 of 2004) and it came into effect w.e.f. 10th December 2004. As per the provisions of this regulation, all the broadcasters /multi system operators and their agents/ intermediaries through whom they provide the signals are required not to engage in any practice or activity or enter into any understanding or arrangement, including exclusive contracts with any distributor of TV channels that discriminates against any other distributor of TV channels. A period of 90 days was granted in respect of the contracts already entered into before the provisions regarding non-discrimination in Interconnect Agreements would apply to these contracts. This period of 90 days was given for old contracts to be renegotiated and brought in compliance with the new regulations.

2. A proposal was received from a broadcaster to extend the transition period for another 60 days to enable all the agreements to be compliant

706 97/2005-2

with the regulations. The reasons given for seeking such an extension are: -

(a) The broadcaster has more than 6000 contracts with various distributors of TV channels that got signed at different points in time. In addition to the above, before the enforcement of the Interconnection Regulation, they had launched several new channels and signed up addendums/ contracts with various operators.

(b) They are now working towards transitioning their various contracts and addendums to make them compliant with the Interconnection Regulation. In addition several internal organizational activities are being implemented to ensure that the transition is entirely smooth, such as

- Formulation of a Policy for distribution of its channels in India to clearly articulate to the distribution personnel the Company's position on various issues related to distribution with step by step instructions on ensuring all activities are compliant with the Interconnection Regulation.
- Review of existing contracts and addendums. On finalization of Distribution Policy, the existing contracts and addendums will be modified to comply with the Policy. The 6000+ contracts will then be re-signed in the modified formats to the extent required and subject to negotiations with their associates.
- Several workshops have already been conducted for distribution personnel and distributors across the country to help them understand the provisions of Interconnection Regulation. The inputs received from these workshops will be used to resolve outstanding issues and queries. Company executives are being briefed in detail regarding the process to be followed for executing the commercial arrangements.
- Organizational processes and systems are being defined to streamline all new activities required to be undertaken by the Company to comply with all the provisions of Interconnection Regulation.

3. The Authority had considered the request to extend the transition period for another 60 days and in line with its consultative approach, it decided to seek comments on the proposed extension of the transition period from 90 days to 150 days. A Press Release was accordingly issued on 11th February 2005 seeking comments in the matter till 18th February 2005. The following are the major comments have been received on the issue:-

(a) Jaipur Cable & Broadband Society has stated that increase in transition period will have adverse effect on those cable channel distributors who raised their voice against broadcaster/ MSO monopolies. By giving more time broadcasters/ MSO will have enough time to manipulate things on the ground. It will delay the

upcoming competition in the market. It has further said that there is only one MSO in Jaipur and it is capturing cable networks by increasing connectivity amount. Extension of transition period by 60 days would mean that broadcasters would not give decoders to cable operators for 150 days and it will be difficult to sustain 150 days without Pay channels.

(b) Cable Operators Federation of India has objected to the proposal for the following reasons:-

- All the major broadcasters have made alliance with each other for distribution whereby they are distributing channels in bouquets through a joint distribution staff.
- It is not true that they are unable to renew their contracts as per the new terms in 90 days as the broadcasters have a very large distribution department comprising of distribution heads, regional managers, area managers and distribution executives in each major town. Apart from this, there are distribution companies in every major city who deal with LCOs. Thus at a lower level, a distributor may not have to deal with more than 40-50 contracts in 90 days.
- The broadcasters are not taking any interest in revising their contracts with existing operators and they are busy in forcing the cable networks to increase their connectivity by 40-60% by appointing minimum guarantee agents in each area. Additional 60 day period will give opportunity to these minimum guarantee agents and their affiliated MSOs to extract the maximum from the existing cable operators.

4. The additional time period of 30 days being granted by this amendment is considered adequate by the Authority for the reason that in case any complaint of a discriminatory interconnection agreement is received by the Authority, the broadcasters /multi system operators/ their agents/ intermediaries would be given an opportunity of explaining their position and rectifying the same. This would give them an opportunity to make such a contract compliant with the Interconnection Regulation.

5. Although the Authority had earlier approved only 90 days for the transition period it is considered that in view of difficulties experienced by the broadcasters and the steps taken so far a further extension of 30 days can be given. Moreover, this is only a one time provision and will have no long term impact. On the other hand if all preparations are not completed there could be unnecessary litigation.

6. Therefore, after considering the proposal and the objections, the Authority decided to extend the transition period from 90 days to 120 days.